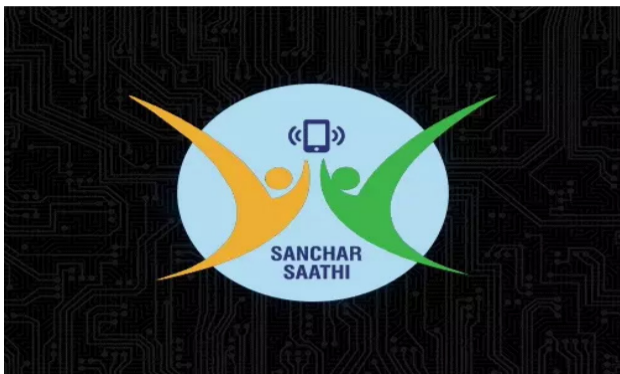


मोबाइल में देना होगा साइबर सिक्योरिटी एप:सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी, संचार साथी' एप से गुम हुए 7 लाख फोन मिले



24 न्यूज अपडेट

अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' प्री-इंस्टॉल (पहले से डाउनलोड) मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी एप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ये आदेश आज सामने आया है। इसमें एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस एप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह एप इंस्टॉल जाएगा।

हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, बल्कि चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है।

इसका मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, 'यह एप फर्जी IMEI से होने वाले स्कैम और नेटवर्क मिसयूज को रोकने के लिए जरूरी है।'

संचार साथी एप क्या है, कैसे करेगा मदद

संचार साथी एप सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है, जो 17 जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था।

अभी यह एपल और गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब नए फोन पर यह जरूरी होगा।

एप यूजर्स को कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप चैट रिपोर्ट करने में मदद करेगा।

IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए फोन को ब्लॉक करेगा।

डुप्लीकेट IMEI नंबर से बढ़ रहा

साइबर क्राइम

भारत में 1.2 अरब से ज्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन फर्जी या डुप्लीकेट IMEI नंबर की वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। IMEI एक 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है, जो फोन की पहचान करता है।

अपराधी इसे क्लोन करके चोरी के फोन को ट्रैक से बचाते

हैं, स्कैम करते हैं या ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। सरकार का कहना है कि यह एप पुलिस को डिवाइस ट्रेस करने में मदद करेगा। सितंबर में DoT ने बताया था कि 22.76 लाख डिवाइस ट्रेस हो चुके हैं।

कंपनियों पर असर, ऐपल-सैमसंग को दिक्कत हो सकती

इंडस्ट्री सोर्सज कहते हैं कि पहले से कंसल्टेशन न होने से कंपनियां परेशान हैं। खासकर एपल के लिए मुश्किल है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी में गवर्नमेंट या थर्ड-पार्टी एप प्री-इंस्टॉलेशन पर पाबंदी है।

पहले भी एपल का एंटी-स्पैम एप पर रेगुलेटर से टकराव हुआ था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एपल सरकार से नेगोशिएशन कर सकती है। एपल यूजर्स को वॉलंटरी प्रॉम्प्ट देने का सुझाव भी दे सकता है। हालांकि, अभी तक किसी भी कंपनी ने आदेश के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है।

यूजर्स की सीधा फायदा मिलेगा

यूजर्स को सीधा फायदा मिलेगा। चोरी का फोन होने पर IMEI चेक करके तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे। फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने से स्कैम कम होंगे, लेकिन एप डिलीट न होने से प्राइवैसी ग्रुप्स सवाल उठा सकते हैं।

यूजर कंट्रोल कम होगा। भविष्य में एप और फीचर्स जुड़ सकते हैं, जैसे बेहतर ट्रैकिंग या AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन। DoT का कहना है कि यह टेलीकॉम सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा।

रुपया 89.79 तक गिरा, सबसे निचले स्तर पर:विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे; डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ा



24 न्यूज अपडेट

रुपया आज (23 सितंबर) डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान रुपया 34 पैसे गिरकर 89.79 के स्तर पर आ गया था। यह 2 हफ्ते पहले के ऑल-टाइम लो (89.66) को पार कर गया। 21 नवंबर को रुपया 98 पैसे गिरा था। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। सुबह रुपया 89.45 प्रति डॉलर के स्तर पर खुला था। वहीं शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ 89.45 पर बंद हुआ था।

2025 में अब तक रुपया 4.77% कमजोर हुआ
रुपया 2025 में अब तक 4.77% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 89.79 के लेवल पर पहुंच गया है।

रुपए में गिरावट से इम्पोर्ट करना महंगा होगा
रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इम्पोर्ट महंगा होना है। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो गया है।

मान लीजिए कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 50 थी, तब अमेरिका में भारतीय छात्रों को 50 रुपए में 1 डॉलर मिल जाता था। अब 1 डॉलर के लिए छात्रों को 89.79 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इससे छात्रों के लिए फीस से लेकर रहना-खाना और अन्य चीजें महंगी हो जाएंगी।

ऑलटाइम हाई बनाकर गिरा बाजार:संसेक्स 65 अंक नीचे 85,642 पर बंद, निफ्टी भी 27 अंक लुढ़का; FMCG और फार्मा सेक्टर में बिकवाली



24 न्यूज अपडेट

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 1 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट रही। संसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 27 अंक की गिरावट रही, ये 26,176 पर बंद हुआ।

इससे पहले शुरुआती कारोबार के दौरान संसेक्स ने 86,159 और निफ्टी ने 26,325 का ऑलटाइम हाई बनाया था। संसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट रही। आज FMCG, फार्मा और फाइनेंस शेयर्स में गिरावट रही। वहीं ऑटो और IT शेयर्स में बढ़त रही।

सोना 2,209 बढ़कर 1.29 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ:इस साल 52,638 महंगा हो चुका, चांदी आज 10,821 चढ़कर 1.75 लाख किलो हुई



24 न्यूज अपडेट

सोने-चांदी के दाम में आज यानी 1 दिसंबर को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम सोना 2,209 रुपए महंगा होकर 1,28,800 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोना 1,26,591 रुपए का था।

वहीं, चांदी 10,821 रुपए महंगी होकर 1,75,180 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी की कीमत 1,64,359 रुपए प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था।

CBI देशभर के डिजिटल अरेस्ट केस की जांच करेगी:SC का निर्देश- राज्य सरकारें जांच एजेंसी की मदद करें; कहा- ये तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम



24 न्यूज अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) को देशभर से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पैन इंडिया जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान SC ने सभी राज्यों को डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में CBI की मदद करने के भी निर्देश दिए।

CJI सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इसमें ठग खुद को पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो/ऑडियो कॉल के जरिए पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटिजन को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं।

CJI सूर्यकांत की बेंच ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर

पूछा कि साइबर ठगी में उपयोग हो रहे बैंक खातों को तुरंत ट्रैक और फ्रीज करने के लिए AI और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा।

इससे पहले 3 नवंबर की सुनवाई में SC ने कहा था कि डिजिटल अरेस्ट मामलों में लगभग 3 हजार करोड़ की ठगी का पता चला है। अदालत ने इसे 'आयरन हैंड' से निपटने लायक गंभीर 'राष्ट्रीय समस्या' बताया था।

दरअसल, हरियाणा के अंबाला जिले में बुजुर्ग दंपति से 3 से 16 सितंबर के बीच 1.05 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। दंपति को सुप्रीम कोर्ट के जजों के फर्जी साइन और जांच एजेंसियों के नकली आदेश दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था। पीड़ित ने 21 सितंबर को CJI बीआर गवई (पूर्व सीजेआई) को चिट्ठी लिखकर पूरी बात बताई थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में खुद से एक्शन लिया था।

सरकार ने माना-देशभर के एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हो रहे:एविएशन मिनिस्टर बोले- विमानों को गलत सिग्नल मिले; दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुईं



24 न्यूज अपडेट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने संसद में माना कि बीते दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर GPS स्पूफिंग (गलत सिग्नल मिलना) की घटना हुई। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्होंने कहा- दिल्ली के अलावा देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी GPS स्पूफिंग और GNSS सिग्नल से छेड़छाड़ की घटनाएं हुईं।

नायडू ने कहा कि वैश्विक स्तर पर रैनसमवेयर-मैलवेयर अटैक का खतरा बढ़ा है। AAI अपने IT और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी अपना रहा है।

नायडू ने राज्यसभा सांसद एस. निरंजन रेड्डी के सवाल का संसद में जवाब दिया। रेड्डी ने पूछा था- क्या सरकार को IGI पर हुई GPS स्पूफिंग की जानकारी है। DGCA-AAI की इससे बचने की क्या तैयारी है।

लोकसभा में वंदे मातरम् पर 10 घंटे चर्चा संभव:पीएम भी हिस्सा ले सकते हैं; केंद्र बोला- SIR पर बहस के लिए तैयार, समय सीमा न थोपें



24 न्यूज अपडेट

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष चर्चा के लिए अड़ा है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील कि वह इस पर कोई समय सीमा न थोपें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'वंदे मातरम्' के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम् पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। यह बहस गुरुवार-शुक्रवार को हो सकती है। पीएम मोदी खुद इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

30 सितंबर को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने इस चर्चा का प्रस्ताव रखा था। अब तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है।

आज सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने संसद के बाहर मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, 'यह सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहां झामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहां जोर नीति पर होना चाहिए, नारों पर नहीं।'

दिल्ली-NCR प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट बोला- सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं:कोविड में भी पराली जलाई फिर भी आसमान साफ था; सरकार एक्शन प्लान पर दोबारा विचार करे



24 न्यूज अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। अदालत ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर आपत्ति जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पराली जलाना नया नहीं है। 4-5 साल पहले कोविड और लॉकडाउन के दौरान भी पराली

जलाई जा रही थी फिर भी आसमान साफ और नीला दिखाई देता था, अब क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि पराली जलाने से जुड़ी बहस को राजनीतिक

या अहंकार का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। दिल्ली की जहरीली हवा के कई कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़ते एयर पॉल्यूशन के पीछे पराली जलाने के अलावा दूसरे कारणों का साइंटिफिक एनालिसिस भी किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

ASG बोलीं- कार्रवाई रिपोर्ट जल्द दी जाएगी

कोर्ट ने CAQM की ओर से पेश हुई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि पराली जलाने के अलावा प्रदूषण बढ़ने के और कौन से प्रमुख कारण हैं।

ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि पंजाब, हरियाणा और CPCB सहित सभी एजेंसियों की कार्रवाई रिपोर्ट जल्द दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को शून्य पराली दहन का लक्ष्य दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ। हालांकि पराली जलाना सिर्फ एक मौसमी कारण है।

जस्टिस बागची ने कहा कि निर्माण कार्य भी प्रदूषण का बड़ा कारण है और पूछा कि निर्माण पर लगा प्रतिबंध जमीन पर कितना प्रभावी रूप से लागू हो रहा है।

कोर्ट ने कहा कि वह प्रदूषण मामले पर हर महीने कम से कम दो बार सुनवाई करेगी। कोर्ट ने माना कि सर्दियों के बाद हालात कुछ बेहतर होते हैं लेकिन अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इतिहास खुद को दोहराएगा।

संपादकीय : वृद्धि की दर

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आने वाली सकारात्मक खबरें निश्चित तौर पर एक राहत का संदेश होती हैं। खासतौर पर जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय उथल-पुथल के बीच देश कई विपरीत स्थितियों का सामना कर रहा हो, आर्थिक विकास दर में सामान्य से अधिक बढ़ोतरी के आंकड़े बताते हैं कि अगर समाधानमूलक उपायों को लागू करने को लेकर संजीदगी वस्ती जाए, तो रास्ते निकाले जा सकते हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में 8.2 फीसद बढ़ी, जो पिछली छह तिमाहियों का उच्चतम स्तर है। यह वृद्धि करीब सात फीसद के अनुमान अधिक है। दरअसल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, कारखाना उत्पादन में तेजी और सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन के बेहतर नतीजे सामने आए। सही है कि इस समय कृषि क्षेत्र सुस्ती के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कारखाना उत्पादन और सेवा क्षेत्र में तेज प्रगति देखी गई, जिसने कृषि क्षेत्र में आई शिथिलता को बेअसर कर दिया। जाहिर है, जीडीपी वृद्धि दर के ताजा सरकारी आंकड़े को आर्थिक मोर्चे पर एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अगर इसका असर जमीनी स्तर पर भी स्पष्ट दिखे और जनता को उसका लाभ सीधे महसूस हो, तभी इसका कोई अर्थ है। निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शुल्क नीति के दायरे में भारत भी है और इससे इसके निर्यात क्षेत्र पर खासा प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग जगहों पर युद्धों और अन्य अनिश्चितताओं के कारण भी बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगातार बचाव

विलुप्ति के बीच

भारत में कई जीव-जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। इस बीच पूर्वोत्तर में हाल ही में उभयचर जीवों की तेरह नई प्रजातियों के अस्तित्व की खोज वास्तव में राहत भरी है। मानव समाज विविध एवं गहन पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है और जब जीवों की प्रजातियां कम या खत्म होने लगती हैं, तो इस तंत्र की कड़ियां भी टूटने लगती हैं। वर्तमान में भले ही इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नजर न आए, लेकिन भविष्य में इसका नतीजा निश्चित रूप से भयावह रूप में सामने आएगा। जिन उभयचरों की नई प्रजातियां मिली हैं, उनमें से छह अरुणाचल प्रदेश, तीन मेघालय और एक-एक असम, मिजोरम, नगालैंड तथा मणिपुर में पाई गई हैं। जाहिर है कि ये प्रजातियां कभी अच्छी-खासी तादाद में रही होंगी, लेकिन पर्यावरण में बदलाव, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से उपजी स्थितियों के कारण इनकी संख्या इतनी कम हो गई कि ये वर्षों तक इंसानी नजर से भी ओझल रहें। दरअसल,

या जदोजहद की स्थिति से गुजर रही हैं। ऐसे में अगर भारत ने वृद्धि दर के मोर्चे पर अनुमान से अधिक हासिल किया है तो यह अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। मगर सवाल यह है कि जिस महंगाई दर के आंकड़े के आधार भी वृद्धि दर के आंकड़े में शामिल माने जाते हैं, क्या उसमें वास्तव में इतनी कमी आई है ? महंगाई दर के कम होने को लेकर सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के बरक्स यह छिपा नहीं है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों के मामले में आम लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी है। यह बेवजह नहीं है कि सरकार के ताजा आंकड़ों पर कुछ सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक निजी निवेश और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वास्तविक उछाल नहीं आता, तब तक ऐसे आंकड़े टिकाऊ नहीं हो सकते। दूसरी ओर, सरकार की ओर से जीडीपी वृद्धि दर को लेकर ये आकलन ऐसे समय जारी किए गए, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ ने अपनी एक रपट में भारत की अर्थव्यवस्था के वार्षिक मूल्यांकन में यहां के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों में गंभीर खामियां बताते हुए इन्हें 'सी' श्रेणी में रखने की बात कही है। आंकड़ों की गुणवत्ता के लिहाज से इसे दूसरा सबसे निचला स्तर माना जाता है। आइएमएफ की रपट चिंता का कारण इसलिए भी है कि इसकी रपटों के आधार पर कई बार उपलब्धियों को सकारात्मक बताया जाता है, तो इसकी ओर से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ताजा आकलन को किस संदर्भ में देखा जाएगा। जो हो, जीडीपी वृद्धि दर को लेकर एनएसओ के आंकड़े अगर अर्थव्यवस्था के वास्तविक धरातल पर सही हैं, तो यह देश के लिए राहत की बात है।

पशु-पक्षियों और अन्य जीवों की कई प्रजातियों का विलुप्त होना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश का सूचक है और इस मसले को हर स्तर पर गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश की जैव विविधता का नियमित तौर पर दस्तावेजीकरण होना चाहिए, ताकि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों को पहचान कर उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें। इस संकट की गहराई का आकलन संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच की एक रपट से किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में कशेरुकी यानी रीढ़ वाले जीवों की 680 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और करीब दस लाख प्रजातियों पर इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। भारत में गौरैया चिड़िया भी इसी संकट से गुजर रही है। अलग-अलग रपटों के मुताबिक, चालीस वर्षों में देश में गौरैया की तादाद साठ-पैंसठ फीसद तक कम हो गई है। कुछ वर्ष पहले तक गौरैया के संरक्षण के लिए कई स्तरों पर विशेष मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन वक्त के साथ ये प्रयास दम तोड़ते नजर आ रहे हैं।

एमबी अस्पताल के ठेका सफाईकर्मियों का प्रदर्शन: न समय पर वेतन, न पीएफ-ईएसआई का अता-पता, धरना-प्रदर्शन की चेतावनी



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल में कार्यरत ठेका सफाईकर्मियों ने सोमवार सुबह विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा और भविष्य निधि (पीएफ) तथा ईएसआई का अंशदान तकरीबन आठ-नौ महीनों से लंबित है। इससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शन के बाद ठेका संघर्ष समिति, उदयपुर तथा राष्ट्रीय ठेका मजदूर संघ (BMS संबद्ध) के प्रतिनिधियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन को ज्ञापन सौंपा।

समय पर वेतन न मिलने और उपस्थिति में गड़बड़ी का आरोप
सफाईकर्मियों ने दावा किया कि निविदा शर्तों के अनुसार वेतन हर माह की 7 तारीख तक मिलना चाहिए, लेकिन पिछले कई महीनों

से नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा। पीएफ और ईएसआई जमा न होने से कर्मचारियों को राजकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार हाजिरी लगने के बावजूद ठेका स्टाफ की उपस्थिति में “एब्सेंट” दिखा दिया जाता है, जिससे नौकरी पर संकट मंडरा रहा है।

वर्दियां न मिलने और 8-8 घंटे की पारी लागू करने पर भी आपत्ति
कर्मचारियों ने बताया कि अब तक उन्हें निर्धारित वर्दियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इसके अलावा अधीक्षक द्वारा ठेका कर्मियों के लिए 8-8 घंटे की पारी लागू करने के आदेश पर भी आपत्ति जताई गई है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान इयूटी व्यवस्था ही बहाल रखी जाए।

नर्सिंग स्टाफ पर उत्पीड़न का आरोप
ज्ञापन में कुछ नर्सिंगकर्मियों पर भी आरोप लगाए गए कि वे मूल

कार्य के बजाय ठेका सफाईकर्मियों की निगरानी करते हैं, उन पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, तथा वार्ड स्टाफ से कहकर कर्मचारियों की उपस्थिति कटवा देते हैं। इससे ठेका कर्मियों में असंतोष बढ़ रहा है।

पीएफ—ईएसआई तीन माह से लंबित, कर्मचारी बोझ तले दबे

ठेका फर्म द्वारा पिछले तीन महीनों से पीएफ और ईएसआई अंशदान जमा नहीं करने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि भविष्य निधि का लेखा-जोखा न होने से उनका वित्तीय भविष्य प्रभावित हो रहा है।

समय पर समाधान नहीं मिला तो आंदोलन की चेतावनी

संघ ने अधीक्षक को चेताया कि यदि मांगे समय पर पूरी नहीं की गईं तो ठेका कर्मी आगामी दिनों में धरना-प्रदर्शन करेंगे। साथ ही, यदि हर माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं हुआ, तो अगले दिन यानी 8 तारीख को सभी ठेका कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। समिति ने कहा कि सफाई व्यवस्था चरमराने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी।

वनरक्षक बने वन-भक्षक एसीबी ने खैरवाड़ा रेंज के दो वनरक्षकों को 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जंगलों की रक्षा की शपथ लेने वाले दो वनरक्षक तब वन-भक्षक बन बैठे, जब लालच ने उनका नैतिक पतन उजागर कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर इकाई ने खैरवाड़ा वन रेंज के कातरवास वन नाके पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वनरक्षकों—महेश कुमार मीणा और विजेश अहारी—को 80,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि ब्यूरो को परिवादियों की ओर से शिकायत मिली थी कि वे नीलगिरी व सेमल की लकड़ी के वैध व्यापार से जुड़े हैं। परिवारी की दो गाड़ियां—एक फलासिया से और दूसरी झाड़ोल से—लकड़ी लेकर खैरवाड़ा जा रही थीं। दोनों के पास विधिवत बिल थे, लेकिन 30 नवंबर की सुबह वन विभाग के कातरवास नाके पर दोनों ट्रकों को रोक लिया गया। आरोप है कि बिना किसी वैधानिक कार्यवाही के, वाहन RJ 09 AU 1283 को छोड़ने के एवज में दोनों वनरक्षक 80 हजार रुपये की रिश्वत की मांग पर अड़े थे। शिकायत की

पुष्टि के बाद एसीबी ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई शुरू की। आज, सोमवार को उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में और डूंगरपुर एसीबी प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित (डीएसपी) के नेतृत्व में ईस्पेक्टर राजेंद्र सिंह व टीम ने दोनों आरोपी वनरक्षकों को रिश्वत लेते ही धर-दबोचा। नोटों पर रासायनिक परीक्षण सहित समस्त कार्रवाई मौके पर की गई। महानिदेशक ने बताया कि यह कार्रवाई साबित करती है कि वन संपदा की सुरक्षा के नाम पर यदि कोई अधिकारी घूस की दरखास्त करेगा तो एसीबी उसे बख्शेगी नहीं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एसीबी) स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

नेशनल हाइवे पर गुजरात नंबर की कार से 2.262 किलो डोडा चूरा सहित तस्कर गिरफ्तार



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान ऋषभदेव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नेशनल हाइवे 48 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर 2 किलो 262 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस ने गुजरात नंबर की स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर यह कार्रवाई

पर पीपली A पुलिस के नीचे वाहन को रोक लिया। वाहन की जांच में डिक्की में छुपाकर रखा गया अफीम डोडा चूरा मिला। कार चालक की पहचान जुजाराम पुत्र चेतनराम (30) निवासी आडेल, भाम्भुओं का मोहल्ला, थाना राबली नाड़ी, जिला बाड़मेर के रूप में हुई। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ थाना ऋषभदेव में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 और 29 के तहत मुकदमा नंबर 291/2025 दर्ज किया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मादक पदार्थ कहाँ से लाया गया और इसकी सप्लाई किन क्षेत्रों में की जानी थी। कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक जोरावर सिंह के साथ कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, दशरथ सिंह और थानाधिकारी बाबलवाड़ा गणपत सिंह शामिल रहे, जिन्होंने मौके पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पंजाब राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने लिया आचार्य महाश्रमण का आशीर्वाद



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर 1 दिसम्बर। तेरापंथ धर्मसंघ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य महाश्रमण अपनी धवल वाहिनी के साथ श्रद्धा, भक्ति, त्याग, शौर्य, और बलिदान की वीर वसुंधरा मेवाड़ में अहिंसा यात्रा के माध्यम से नशामुक्ति , नैतिकता और सद्भावना का संदेश देते हुए विभिन्न क्षेत्रों का विचरण करते हुए धर्म प्रभावना कर रहे हैं। श्री मेवाड़ जैन श्वेताम्बर तेरापंथी कांफ्रेंस के अध्यक्ष राजकुमार फत्तावत ने बताया कि फत्तावत ने बताया कि प्रातः स्टोनाइट मार्बल पर पंजाब के राज्यपाल और चण्डीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य महाश्रमण और गुलाबचंद कटारिया में आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। पंजाब के राज्यपाल और चण्डीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया का साहित्य सम्पर्ण उपरना

नेक्सस सेलिब्रेशन में लॉन्च हुआ ‘वेलोसिटी’ 24 न्यूज अपडेट

उदयपुर : नेक्सस सेलिब्रेशन ने अपने रोमांचक समर एक्टिवेशन ‘वेलोसिटी’ का अनावरण किया। रेंसिंग थीम पर आधारित इस रोमांचक अनुभव को बच्चों और बड़ों—दोनों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें एक्शन से भरपूर चुनौतियाँ और आकर्षक विजुअल जोन्स शामिल हैं। यह पूरा कॉन्सेप्ट परिवारों को मजा, एडवेंचर और साथ में समय बिताने का शानदार मौका देता है। इसकी एंट्री शुल्क केवल 150 से शुरू हो रही

है। विजिडर्स के लिए कई इंटरैक्टिव ज़ोन बनाए गए, जिनमें साइकल रेस, सॉर्ट-इट चैलेंज, एक्कवेशन एरीना और रंग-बिरंगा ग्रैंड प्रिक्स ज़ोन शामिल हैं। हर एक्टिविटी को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे पूरे समय उत्साहित रहें, जबकि माता-पिता भी उनके साथ जुड़कर यादगार पल बना सकें। अपने डायनेमिक सेटअप, आकर्षक डिजाइन और एड्रेंनालिन से भरे अनुभवों की बदौलत वेलोसिटी इस सीजन में परिवारों के लिए एक लोकप्रिय एडवेंचर डेस्टिनेशन बन गया है।

प्रो. दिग्विजय भटनागर को एमएलएसयू केंद्रीय पुस्तकालय का नया प्रभारी अधिकारी बनाया



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार इतिहास विभाग की प्रोफेसर दिग्विजय भटनागर को विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

एमएलएसयू कर्मचारी संघ ने नए कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत का स्वागत किया



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ) ने सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर बी.पी. सारस्वत का पारंपरिक मेवाड़ी सम्मान के साथ स्वागत किया। संघ पदाधिकारियों ने कुलगुरु को मेवाड़ी पगड़ी और उपर्णा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। कर्मचारी संघ ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय में सकारात्मक कार्यसंस्कृति और कर्मचारी हितों को बढ़ावा देने की आशा व्यक्त की। संघ प्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व कुलगुरु प्रो. सुनीता मिश्रा की कर्मचारी-विरोधी नीतियों और मेवाड़ के इतिहास पर की

गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में लगभग एक वर्ष तक लगातार संघर्ष किया गया। संघ का कहना है कि इसी क्रम में माननीय राज्यपाल द्वारा पूर्व कुलगुरु को पदमुक्त करते हुए नए कुलगुरु को नियुक्त किया गया है। नए कुलगुरु का स्वागत करने वालों में संघ के संरक्षक अरविंद सिंह राव, प्रतीक सिंह राणावत, संघ अध्यक्ष नारायण लाल सालवी, आदित्य पांडे, मुकुल, योगेश पालीवाल, मनीष बंसल, दिनेश गुर्जर, विजय शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ ने कुलगुरु से अपेक्षा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी-हैतिमी वातावरण स्थापित होगा और शैक्षणिक-प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा और पारदर्शिता आएगी।

डॉक्टर साहब के पक्ष में चली 'जन आक्रोश की मिसाइलें', फुस्स हो गए पॉलिटिकल सूतली बम!!

24 न्यूज अपडेट



उदयपुर। बड़गांव में डॉक्टर अशोक शर्मा के जयपुर तबादले का आदेश क्या आया, पूरा कस्बा भावनाओं के ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। एक ओर डॉक्टर को हटाने पर जश्न मनाने की नीयत से कुछ राजनीतिक अवसरवादी अस्पताल के बाहर पटाखे फोड़कर अपनी 'सूतली राजनीति' का प्रदर्शन करते दिखे, वहीं दूसरी ओर आज फिर हजारों लोगों की भीड़ डॉक्टर के समर्थन में उमड़ पड़ी। लोगों का यह सैलाब उन पटाखों की आवाज पर ऐसी भारी पड़ा कि आतिशबाजी की चमक एक झटके में जन आक्रोश की मिसाइलों के आगे फीकी पड़ गई। बड़गांव की जनता ने साफ संदेश दे दिया—अब पॉलिटिकल सूतली बम फुस्स हो चुके हैं।

पॉलिटिकल आतिशबाज तब कहां होते हैं जब कोई होता है ट्रेप

अस्पताल के बाहर हुई आतिशबाजी पर जनता ने तर्क दिया कि था कि यह जश्न किस

बात का? एक सरकारी आदेश पर राजनीति की जरूरत क्या है? लोगों का मानना था कि अस्पताल के बाहर पटाखे छोड़ने से नेताओं की छवि बेहतर बनने के बजाय और खराब हुई है। जनता का दर्द यही था कि अस्पताल चुनावी मंच नहीं है, और मरीजों की पीड़ा किसी सूतली बम से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। जो लोग आतिशबाजी कर चिकित्सा व्यवस्था का मजा देखना चाहते हैं वे उस समय कहां होते हैं जब कोई रिश्तखोर सीएमएचओ दफतर में ही ट्रेप होता है या फिर जन समस्याओं के लिए लोग खुद ही जूझ रहे होते हैं??

जमीन पर बैठकर सुनी एसडीएम ने मन की बात

आज फिर बड़गांव सेटेलाइट हॉस्पिटल का माहौल किसी जनआंदोलन की तरह था। बच्चे, महिलाएँ, युवाओं से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग तक—हर कोई डॉक्टर के जाने की खबर सुनते ही रो पड़ा। डॉक्टर जैसे ही बाहर आए, किसी बच्चे ने उनका हाथ पकड़ लिया, कोई बुजुर्ग उनके पैरों में बैठ गया, कोई महिला रोती हुई बोली—“डॉक्टर साहब, आप नहीं जाओ आपके बिना कौन देखेगा?” यह दृश्य देखकर एसडीएम लतिका पालीवाल ने भी जमीन पर बैठकर डॉक्टर से बात कर हाल समझा।

मेरे यहां नेता भी लगते हैं लाइन में

रिलीव होकर बाहर आते वक्त डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने कभी नेता-अमीर-गरीब में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने करोड़पतियों

और नेताओं तक को लाइन में खड़ा किया और उन्हें सिखाया कि उनकी वैल्यू भी आम आदमी से ज्यादा नहीं है। यही साफगोई शायद कुछ राजनीतिक लोगों को खटक गई। डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर भी स्पष्ट लिखा—“ये पूरी बीजेपी नहीं कुछ स्वार्थी लोग हैं। इन्हें गरीब की चिंता नहीं, अपनी दुकानदारी की चिंता है।”

सूरमाओं का बन गया मजाक

डॉक्टर के हटने पर आतिशबाजी कर 'सूरमा' बनने की कोशिश करने वाले नेता आज सोशल मीडिया पर मजाक बन चुके हैं। लोग खुलकर कह रहे हैं—“जिन्हें लगा था कि एक रात की आतिशबाजी से माहौल उनके पक्ष में जाएगा, वे भूल गए कि जनता की आंखों में आंसू थे, और आंसूओं का पानी सूतली बम को जलने नहीं देता।” ग्रामीणों की आवाज भी स्पष्ट रही कि यहां बड़े डॉक्टर डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन इलाज तो शर्मा जी का ही लगता है। उनकी दवाई दो दिन में असर करती है। वे प्यार से देखते हैं, डांट-फटकार नहीं। एक महिला का गंभीर बयान वायरल हो गया जिसमें उसने कहा कि मैं निजी डॉक्टर के घर काम करती हूँ, पर इलाज यहां करवाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर शर्मा ने तीन बार मेरी जान बचाई है।

सोशल मीडिया पर जबर्दस्त समर्थन

डॉक्टर शर्मा की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता भी उनके पक्ष में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इंस्टाग्राम पर उनके 3.10 लाख फॉलोअर हैं, और वे सामान्य

मरीजों की कहानियाँ बड़ी सहजता से साझा करते थे। चर्चा यह भी है कि यही 'प्रभावशाली छवि' कुछ नेताओं को रास नहीं आई। गुस्से का उबाल इतना था कि आज अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर संचालकों से भी भिड़ंत हो गई। दो सप्ताह पहले CMHO ने दो मेडिकल स्टोर पर अवैध क्लिनिक चलाने का छापा मारा था, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा आज फिर भड़क उठा और पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा।

गुरुजी का फोटो उठाते ही फूट-फूट कर रोने लगे लोग

डॉक्टर जब अपने कक्ष से गुरुजी की फोटो और गाय माता का प्रतीक चिह्न लेकर बाहर निकले, तो पूरा बड़गांव सिसक उठा। महिलाएँ वाहन के आगे खड़ी हो गईं, बच्चे रोते हुए उनसे चिपक गए। यह दृश्य किसी विदाई का नहीं, विश्वास टूटने का था।

निष्कर्ष यही है—जनता ने साफ कह दिया है कि उनकी भावनाओं की मिसाइलें किसी भी राजनीतिक सूतली बम से ज्यादा ताकतवर हैं। बड़गांव ने साबित किया कि जनता का विश्वास किसी आदेश, किसी राजनीति, किसी आतिशबाजी से बड़ा है। डॉक्टर शर्मा के प्रति जनता का प्यार सिर्फ समर्थन नहीं, एक संदेश है—जिस पर जनता भरोसा करती है, उसे राजनीति की बलि नहीं चढ़ने देंगे। और यही कारण है कि—शर्माजी के पक्ष में चली जन आक्रोश की मिसाइलें, किसी भी राजनीतिक सूतली बम से हजार गुना ज्यादा घातक और प्रभावशाली साबित हुई हैं।

दशा हुमड़ दिगंबर जैन समाज ने सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने का लिया निर्णय



24 न्यूज अपडेट

सागवाड़ा (जयदीप जोशी)। भारतवर्षीय 18 हजार दशा हुमड़ दिगंबर जैन समाज की हाई-पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी एवं नव-निर्वाचित महासभा के अध्यक्षों की विशेष बैठक में समाज द्वारा अगले वर्ष सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने

तथा विवाह समारोह में पत्रिका बांटने, गिफ्ट देने, प्री-वेडिंग शूट के फोटो जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश खोड़निया की अध्यक्षता में, संरक्षक बसंतलाल सराफ, मोहनलाल पिंडरमिया, धनपाल लालावत, चंदमल खोड़निया, प्रमोद शाह, धनपाल शाह के आतिथ्य में दशा हुमड़ शिक्षण संस्थान वगैरी में आयोजित

हुई। बैठक का प्रारंभ महासचिव साधना कोठारी ने अतिथियों का शब्दों से स्वागत कर किया। बैठक में आगामी वर्ष में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव लिया गया। विवाह समारोह में गांव-गांव जाकर पत्रिका बांटने से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए अब व्हाट्सएप या मोबाइल संदेश के जरिए सूचना देते, शादी में गणेश व हल्दी में अनावश्यक खर्च रोकने, गिफ्ट देने पर रोक लगाने एवं सामाजिक मर्यादाओं के अनुरूप प्री-वेडिंग शूट के फोटो सामाजिक भोजन पंडाल में लगाने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव मुख्य कार्यकारिणी

(प्रतिनिधि सभा) की स्वीकृति हेतु रखने का निर्णय किया गया। संरक्षक बसंतलाल सराफ ने आजकल छोटी-छोटी बातों पर संबंध-विच्छेद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषय पर समाज स्तर पर ठोस कार्रवाई आवश्यक है। इस पर समाज अध्यक्ष खोड़निया ने महिला महासभा की एक समिति बनाने की घोषणा की, जो विवादित परिवारों से संपर्क कर विवाद सुलझाने में सहयोग करेगी। साथ ही जैन समाज में संबंध-विच्छेद पर दंडात्मक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी लिया गया।

प्रेक्टिकल कोर्स प्रारम्भ करने में राजस्थान में सुखाड़िया विश्वविद्यालय अग्रणी”- कुलपति



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय एवं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) के संयुक्त तत्वावधान में वाणिज्य महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में बी.कॉम. कार्यक्रम के तहत संचालित विभिन्न प्रैक्टिकल कोर्सेज पर अकादमिक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। यह कोर्सेज नई शिक्षा नीति (NEP)–2020 के अनुरूप प्रारम्भ किए गए हैं। बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के शिक्षकगण मौजूद रहे।

प्रेक्टिकल शिक्षा मॉडल की शुरुआत 2016–17 में- प्रो. भाणावत

कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत उद्बोधन से हुई, जिसे वाणिज्य संकाय अध्यक्ष एवं IQAC निदेशक प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत ने संबोधित

किया। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल कोर्सेज प्रारम्भ करने का प्रयास वर्ष 2016–17 में ही शुरू कर दिया गया था। आज महाविद्यालय में टैली, एमएस एक्सेल, ERP अकाउंटिंग, SAP अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस कम्प्युनिकेशन सहित कई कौशल-आधारित कोर्स प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं। इन कोर्सेज ने विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

सालों पुराने नोट्स अब काम नहीं

आएँगे- कुलपति का स्पष्ट संदेश

बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत ने की। अपने संबोधन में उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवाचारों को राजस्थान में अग्रणी मॉडल बताते हुए कहा कि प्रैक्टिकल कोर्सेज आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हैं। कुलपति ने घोषणा की कि इस मॉडल को वे अपने कोटा विश्वविद्यालय में भी लागू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा—“अब कक्षाओं में सालों पुराने नोट्स नहीं चलेंगे। हर शिक्षक को विद्यार्थियों को कौशल आधारित और रोजगार-उन्मुख शिक्षा देनी होगी।” वाणिज्य विषय में प्रथम बार प्रयोगात्मक कोर्सेज शुरू करने के लिए उन्होंने

संकाय की प्रशंसा भी की।

प्रस्तुतीकरण और पैनल चर्चा

उद्घाटन सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय की सह-अधिष्ठाता डॉ. शिल्पा वर्डिया ने दिया। इसके बाद लेखांकन एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग की सहायक आचार्य एवं NEP नोडल अधिकारी डॉ. शिल्पा लोढ़ा ने वर्तमान प्रैक्टिकल कोर्सेज की प्रगति पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। पैनल डिस्कशन में शहर के ख्यातनाम चार्टर्ड अकाउंटेंट—सीए कमल खुर्दिया, सीए अरुण पितलिया, सीए हितेश कुदाल, साथ ही विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. मुकेश बारबर शामिल रहे। सिरौही, शिवगंज, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के संबद्ध महाविद्यालयों से आए प्राध्यापकों ने अपने अनुभव एवं चुनौतियाँ साझा कीं। चर्चा का संचालन सीए हेमंत कदूनिया ने किया। पैनलिस्टों ने शिक्षण एवं परीक्षा प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए। पैनल चर्चा के अंत में धन्यवाद ज्ञापन व्यवसाय प्रशासन विभाग के इंचार्ज हेड डॉ. देवेंद्र श्रीमाली ने दिया। कार्यक्रम में डॉ. शैलेन्द्र शिमा राव, डॉ. आशा शर्मा, डॉ. रेनू शर्मा, डॉ. पारूल दशोरा, डॉ. पुष्पराज मीना सहित अनेक शिक्षाविद उपस्थित रहे।

अजमेर मंडल में ओवरचार्जिंग व अवैध वेंडिंग पर सख्ती: 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशेष अभियान



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। रेल यात्रियों को उचित दरों पर स्वच्छ खानपान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने अजमेर मंडल में ओवरचार्जिंग और अवैध वेंडिंग के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके दौरान मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर गहन जांच व सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजमेर मंडल में यह विशेष पहल, मुख्यालय एवं मंडल रेल

प्रबंधक राजू भूतड़ा के निर्देश पर संचालित की जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने अजमेर, आबूरोड, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, फालना, मारवाड़ जंक्शन, मावली जंक्शन और उदयपुर सिटी स्टेशनों के वाणिज्य निरीक्षकों को अपने-अपने खंडों में अचानक निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।

इन बिंदुओं पर होगी

कड़ी निगरानी

खानपान इकाइयों पर किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग पर

तत्काल कार्रवाई प्लेटफॉर्म व ट्रेनों में अवैध वेंडिंग का पूर्ण उन्मूलन वेंडरों और कैटरिंग ठेकेदारों को नई दर सूची प्रदर्शित करने के निर्देश

सभी वेंडरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्यलाइसेंस फीस समय पर जमा करवाना

केवल अधिकृत रेल नीर की विक्री

अनाधिकृत कर्मियों का उपयोग नहीं करने का निर्देश

अभियान के दौरान मण्डल वाणिज्य निरीक्षक नियमित मीटिंग लेकर ठेकेदारों और वेंडरों को रेलवे के खानपान मानकों का पालन सुनिश्चित करा रहे हैं। रेल प्रशासन का दावा है कि इस सख्त कार्रवाई से यात्रियों को गुणवत्ता युक्त और उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने में बड़ा सुधार आएगा।

उदयपुर—पुणे मार्ग पर फाल्कन बस सेवा फिर शुरू, सुरक्षा फीचर्स और आराम में बढ़ोतरी



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। फाल्कन बस ने 1 दिसंबर से अपनी लोकप्रिय उदयपुर-पुणे बस सेवा को दोबारा शुरू कर दिया है। बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए कंपनी ने इस सेवा को कई उन्नत सुरक्षा और आरामदायक फीचर्स के साथ पुनः संचालित किया है।

फाल्कन लंबे समय से मुंबई, उदयपुर और नाथद्वारा के बीच प्रीमियम वोल्वो सेवाओं के लिए जानी जाती रही है। उदयपुर-पुणे सेवा, जिसे 2016 में शुरू किया गया था, परिचालन चुनौतियों के चलते जून 2025 में अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। अब परिस्थितियों में सुधार के बाद इसे फिर से बहाल

किया गया है।

उन्नत वोल्वो 9600 बसें

पुनः शुरू की गई सेवा में वोल्वो 9600 बसों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग, एंटी-स्कड ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड गवर्नर इंजन, CCTV निगरानी, इमरजेंसी अलर्ट और हाई-कम्फर्ट स्लीपर कैबिन जैसे फीचर्स शामिल हैं। फाल्कन बस के सीईओ हार्दिक कोटक ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और विश्वसनीय यात्रा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि “उदयपुर-पुणे सेवा का पुनः संचालन यात्रियों की बढ़ती मांग और सुरक्षित इंटरसिटी यात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

रॉकवुड्स स्कूल में भव्य इंटैक मेवाड़ हेरिटेज फेयर का आयोजन



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। रॉकवुड्स स्कूल एवं इंटैक के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य इंटैक मेवाड़ हेरिटेज फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने राजस्थान की समृद्ध विरासत और लोक संस्कृति को आकर्षक एवं जीवंत प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि इंटैक के चेयरमैन श्री अशोक सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। अतिथियों का

स्वागत मेवाड़ी पग, दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। स्कूल निदेशक डॉ. दीपक शर्मा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए मेवाड़ की धरोहर संरक्षण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इंटैक उदयपुर चैप्टर के संयोजक श्री गौरव सिंघवी ने भी विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। इसके पश्चात मुख्य अतिथि, संस्थान की संरक्षिका श्रीमती अल्का शर्मा तथा निर्णायक मंडल ने विद्यालय की न्यूजलेटर 'निधिदर्पण' का विमोचन किया।

विज्ञान महाविद्यालय में संविधान सप्ताह का भव्य समापन, कुलपति ने दिलवाई शपथ



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 1 दिसम्बर 2025। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में विज्ञान महाविद्यालय द्वारा संविधान सप्ताह का समापन समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत तथा विशिष्ट अतिथि कुलसचिव

डॉ. वी.सी. गर्ग रहे। समारोह का शुभारंभ विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. सी.पी. जैन ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक रहते हुए राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। इसके पश्चात कुलपति प्रो. सारस्वत ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों के साथ संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का सामूहिक पाठ करवाया तथा सभी को संविधान की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवक और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थितों ने न्याय,

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। समारोह के बाद 'संविधान रत्न' का आयोजन हुआ जिसके माध्यम से युवा शक्ति ने राष्ट्रभावना और अनुशासन का संदेश दिया। साथ ही, परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का संचालन भरत कुमार यादव ने किया, जबकि सह-अधिष्ठाता प्रो. एल.एस. चौहान ने आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर डॉ. प्रभात बरोलिया, डॉ. दीपक चौधरी, डॉ. तरुण कुमार, डॉ. अनिता मेहता, डॉ. सुभाष जनाघल, डॉ. देवेंद्र गोयल सहित कई गणमान्यजन उपस्थित रहे।